

दिल्ली के परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त एवं सचिव एसटीए भारत सरकार के बजट में दिए निर्णय से अनभिज्ञ है या जानबूझ कर अनभिज्ञता दिखा रहे हैं, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। भारत देश की वित्त मंत्री द्वारा बजट में यह घोषणा कर दी गई थी की अब देश भर में वाहन की आरसी, वाहन चालकों के लाइसेंस और वाहन कंडक्टर को 1 अप्रैल से बनवाते समय लगने वाली 200 की फीस नहीं ली जाएगी और यह सभी दस्तावेज वाहन मालिकों/चालकों और कंडक्टर को ई प्रक्रिया से प्राप्त होंगे तथा 1 अप्रैल से कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे और इसकी जानकारी हमारे समाचार पत्र में कई बार जनहित को जानकारी हेतु छापी गई थी और इसके अलावा हमने जनहित में यह समाचार भी छापा था की इस आदेश के खिलाफ जयपुर में एक जनहित याचिका भी दायर हुई है और मांथने में अदालत में बताया था की यह नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है क्योंकि यह बजट में ही जारी दिशा निर्देश है। दिल्ली परिवहन विभाग की तो आदत ही है जनता से गैर कानूनी तरीके से आनलाइन आवेदन में

ऐसी बंद की जा चुकी फीस लेते रहना और लेकर राजस्व में इजाफा करवाना जिस के तहत आज तक वाहन मालिकों/चालकों से कार्ड के नाम से फीस लेते जा रहे हैं पर क्या परिवहन विभाग की अपनी शाखाओं में कार्ड जारी किए जा रहे हैं या नहीं की जानकारी विशेष परिवहन आयुक्त ऑपरेशन एवम् सचिव एसटीए को नहीं है, क्या यह सम्भव है। मंत्री एवम् आयुक्त द्वारा जारी डीलरो को आदेश की जल्द से जल्द वाहन मालिकों को आरसी कार्ड जारी करे सिर्फ जनता को गुमराह करने सा है। परिवहन विभाग जनता से फीस के नाम पर बंद की जा चुकी फीस को इस सोच से लेता रहता है कि जितना जब तक पैसा लूटा जा सके लूट लिया जाए और राजस्व में इजाफा करवाया जाता रहे। बजट में वित्त मंत्री की घोषणा के बाद भी कार्ड के नाम से फीस बटोर रहे हैं तो सिर्फ वाहन डीलरो से नहीं अपने कार्यालय में भी रोके हुए कार्ड तत्काल प्रिन्ट करवाकर जारी करवाए।



अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में बन रहा एयरपोर्ट से भी सुन्दर रेलवे स्टेशन

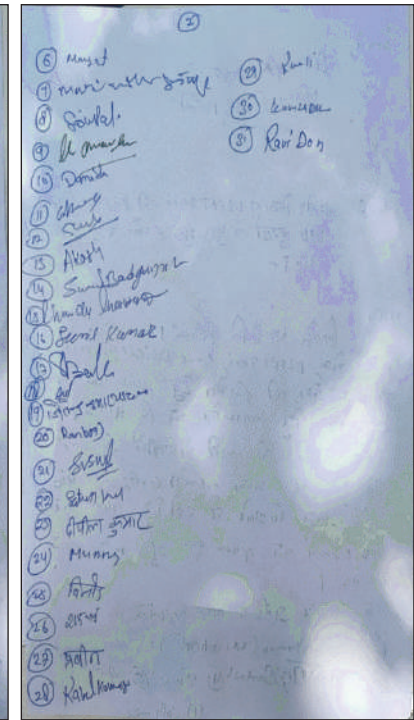
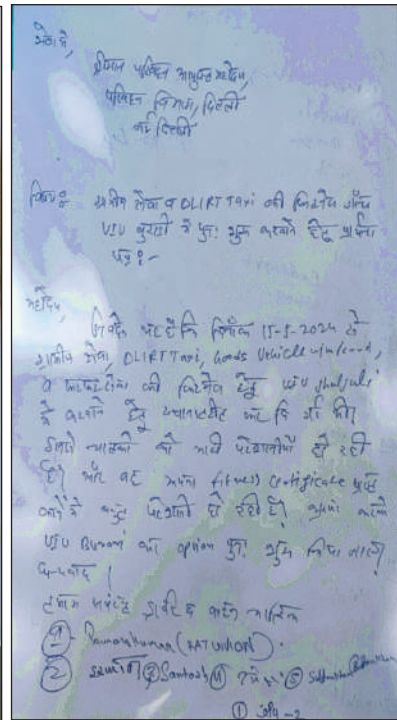
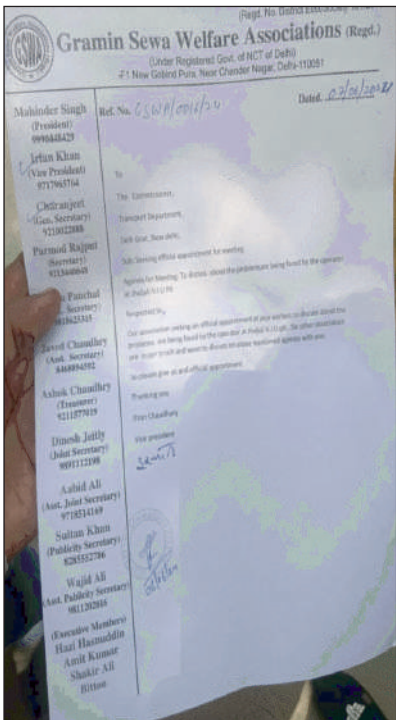
परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आप सभी ने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक सुन्दर एयरपोर्ट देखे होंगे पर अब आप जल्दी ही एयरपोर्ट से भी सुन्दर रेलवे स्टेशन देखेंगे। अयोध्या धाम में ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जो सुन्दर से भी सुन्दर एयरपोर्ट को मात दे देगा। यह खास रेलवे स्टेशन 12 एकड़ से भी अधिक जमीन पर बन रहा है और तीन मंजिल का होगा। इस रेलवे स्टेशन पर वह सारी सुख-सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो आज दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी में खास रेलवे स्टेशन यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी अयोध्या शहर के पास अयोध्या धाम के नाम से बनने वाला यह रेलवे स्टेशन किसी भी एयरपोर्ट से सुंदर बनेगा। इस रेलवे स्टेशन को भारत सरकार की कंपनी राइट्स बना रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आपको क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल के अलावा साफ सुथरा शौचालय, पर्यटक सूचना केंद्र और पूजा की आवश्यकता की दुकानों उपलब्ध होंगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर टेक्सी बे और एक विस्तारित कोर्स भी बनाया जा रहा है। यह रेलवे स्टेशन वर्ष-2025 में बनकर तैयार हो जाएगा, कंपनी ने जनवरी 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यहां पर एक साथ

लगाभग 15 हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी रखी जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की एक विशेषता यह है कि यह राम मंदिर की वास्तुकला से बनाया जा रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी उसी पत्थर से बनाया जा रहा है जिससे भव्य राम मंदिर बनाया गया है। अयोध्या धाम स्टेशन का निर्माण तीन मंजिला है। रेलवे पटरियों के सामने के कोनों पर छत्री शैली की "शिखर" संरचनाएं बनाई गई हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम जनहित में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, पूजा की आवश्यक सामग्री की दुकानों के अतिरिक्त लिफ्ट, एस्केलेटर, शौचालय और पर्यटक जानकारी केंद्र है। स्टेशन पर एक विस्तारित पोर्च और एक टेक्सी बे भी है। 12 एकड़ के इस रेलवे स्टेशन में 15000 यात्रियों की जगह है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग डोरमेट्री बनाई गई है सभी कमरों में एक अटैच टॉयलेट है। कुछ महीनों की प्रतीक्षा के बाद देख सकेंगे एयरपोर्ट से भी सुंदर रेलवे स्टेशन।



ग्रामीण सेवा वेलफेयर एसोसिएशन ने विशेष परिवहन आयुक्त से मुलाकात की



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में चल रही ग्रामीण सेवा और डील 1 आरटी के अंदाजा 20 वाहन मालिक इकट्ठे होकर आज आईपी डिपो डीटीसी हेडक्वार्टर (जहा आजकल दिल्ली परिवहन विभाग के आयुक्त, विशेष आयुक्त, और उपायुक्त बैठ रहे हैं) अपनी परेशानियों के हल के लिए मिलने गए। कार्यालय में उनकी भेट/मुलाकात विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम से हुई और लम्बे समय तक चर्चा हुई पर

जिस समस्या का वाहन मालिको को समाधान चाहिए था उस पर कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें आचार संहिता के चलते वीआईयू बुराड़ी फिटनेस शाखा में जिन वाहनो की फिटनेस हो रही थी उन्हे पूर्व सूचना और पब्लिक नोटिस जारी किए बिना प्राइवेट कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से झुलझुली फिटनेस शाखा में परिवर्तित कर दिया और उसी के विरोध और तत्काल प्रभाव से वापिस वीआईयू बुराड़ी फिटनेस शाखा में करने की बात लेकर गए थे पर

विशेष परिवहन आयुक्त की बातों से पता चला की उन्होने ही यह आदेश सोची समझी रणनीति के अनुसार किया है तो वह मंत्री परिवहन दिल्ली के भी कहने पर क्यों वापिस करने के दिशा निर्देश जारी करे। इसी मुद्दे को पुनः उठाने की लिए ग्रामीण सेवा वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य सहयोगी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा आयुक्त परिवहन से मिलने के लिए समय मांगा है और उनके समक्ष अपनी पूरी परेशानियां बता कर अब हल मांगेंगे।

क्या दिल्ली सरकार का यह आदेश सच में अतिक्रमण से मुक्ति दिला पाएगा या सिर्फ राजस्व बटोरने का हिस्सा बन कर रह जाएगा, बड़ा सवाल?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर के क्षेत्रफल या लंबाई के हिसाब से अतिक्रमण पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है, एमसीडी या डीडीए को दूसरों/जनता को जुर्माना तभी देना होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितना अतिक्रमण किया हुआ है। हालांकि स्वयं राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा गरीबों को बुलाकर अतिक्रमण करवाना और कानून को तोड़ना एक फैशन बन गया है जिसके कारण हर दिन लोग मानसिक आघात झेलते हैं और पीड़ित होते हैं। सड़क पर अतिक्रमण से आवागमन में भारी परेशानी होती है। लोग सड़क पर चल रहे हैं, सड़क

की ओर चल रहे हैं या सड़क के बीच में चल रहे हैं जिससे दुर्घटना का खतरा है। केवल सरकारी विभाग एमसीडी, डीडीए स्थानीय पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा सकती बल्कि हम सभी को इसका ध्यान रखना होगा। सड़कों और सड़कों पर जानवरों को आना-जाना, खड़ा या बैठा रहना, जानवर का वाहनों के सामने कूद पड़ना और दुर्घटनाग्रस्त हो जाना आज कोए कोई खास बात नहीं रह गई इस को रोकने के लिए सरकारी विभागों पर इल्जाम लगाने की जगह हम लोगो को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी क्योंकि आवारा पशुओं को सिर्फ यातायात पुलिस नहीं रोकेगी। आप जिम्मेदारी लेंगे तभी इस समस्या

का समाधान होगा। इस प्रकार के अतिक्रमण से ना सिर्फ जानवरों को चोट पहुंच रही है अपितु हमें ओर हमारे पारिवारिक सदस्यों का जीवन संकट में पड़ रहा है साथ ही मानसिक चोट लग रही है। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि सभी विभागों को मिलाकर इस पर काम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस वाहन का चालाना काट कर अपना कर्तव्य निभाने का दिखावा कर रही है। सड़क सुरक्षा, जाम मुक्त और दुर्घटना मुक्त सड़कें तभी जनता को मिल सकती हैं जब जनता स्वयं और सभी सम्बंधित विभाग आपना काम पूरी ईमानदारी से करें।

ओमनी रोड सेप्टी फाउंडेशन जगमोहन सिंह



दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के प्रतिनिधि अध्यक्ष श्री हरीश गोवर जी, उपाध्यक्ष श्री दिनकर सिंह जी.यु.पी.बॉर्डर प्रभारी श्री अजय जी, महासचिव श्याम सुन्दर यु.पी.बॉर्डर पर कार्यरत हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को हो रही परेशानी को लेकर श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी, सहायक आयुक्त, प्रभारी राज्य कर, गाजियाबाद यु.पी.को अवगत कराया गया जिसको उन्होंने गम्भीरता पूर्वक सुना और हर संभव समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया।

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bhatiasanjaybatlia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेखान 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020)। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, गिंददर्शिना अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कारिपोरट कार्यालय :- 529, समथपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ोदा दिल्ली 110042

सड़क सुरक्षा और पैदल चलने की आदत: आने वाले भविष्य की आवश्यकता

आज के दौर में सड़क सुरक्षा के साथ-साथ पैदल चलने की आदत डालना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आधुनिक परिवहन साधनों की बढ़ती संख्या और लोगों की आरामपसंद जीवनशैली ने सड़क सुरक्षा के मुद्दों को और जटिल बना दिया है। सड़क पर बढ़ती वाहनो की भीड़ के कारण पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

सड़क पर बढ़ती भीड़ और पैदल चलने की मजबूरी

आजकल की स्थिति यह हो गई है कि लोगों ने पैदल चलना लगभग छोड़ दिया है। हर कोई या तो रिक्शा, ऑटो या कार का उपयोग करने लगा है। खासकर बड़े शहरों में, जहां हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, सड़क पर पैदल चलना मानो असंभव हो गया है। इस भीड़भाड़ की स्थिति में पैदल चलना मजबूरी बन गया है, जो न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

वृद्धावन यात्रा का अनुभव

हाल ही में मैंने वृद्धावन की यात्रा की। वहां मैंने देखा कि किस प्रकार लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक तो किया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में पैदल चलने के लिए विवश किया गया है। संकीर्ण गलियों और भीड़भाड़ के कारण लोग चाह कर भी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते। यह स्थिति न केवल उनके लिए असुविधाजनक है, बल्कि उनके पाँकट पर भी भारी पड़ती है। वाहन का खर्चा, पार्किंग की समस्या और सड़क जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है।

पैदल चलने के लाभ

वर्तमान समय में हमें पैदल चलने की आदत को पुनः अपनाने की आवश्यकता है। इसके अनेक फायदे हैं:

स्वास्थ्य लाभ: पैदल चलना एक उत्तम व्यायाम है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हृदय को मजबूत करता है, मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है और तनाव को कम करता है।

पर्यावरण संरक्षण: पैदल चलने से वाहनो का उपयोग कम होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

आर्थिक बचत: पैदल चलने से वाहन ईंधन और पार्किंग खर्च में बचत होती है। इससे पाँकट पर बोझ भी कम पड़ता है।

सामाजिक लाभ: पैदल चलने से आप अधिक लोगों से मिल सकते हैं, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और सामुदायिक भावना बढ़ती है। अतः यह आवश्यक है कि हम सड़क सुरक्षा

के साथ-साथ पैदल चलने की आदत डालें। यह हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति के लिए लाभकारी होगा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना और पैदल चलने की आदत डालना, आने वाले भविष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम न केवल सुरक्षित रह सकें, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकें।

indiangreenbuddy@gmail.com

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली के चारों तरफ हुई किलेबंदी, जानें किन-किन चीजों पर लगी पाबंदी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। कल यानी रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को नो फ्लाईंग ज़ोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू की जाएगी। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात होंगी. एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की तैनाती होगी. शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरीशस और सेशेल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. शहर के लीला, ताज, आईटीसी मौर्या, क्लेरिजेस और ओबेरॉय जैसे होटलों को पहले ही सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।

‘हाई अलर्ट’ पर राष्ट्रीय राजधानी, 3 लेयर की सुरक्षा

अधिकारियों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी ‘हाई अलर्ट’ पर रहेगी. समारोह के दिन दिल्ली पुलिस के स्वाट और एनएसजी के कमांडो राष्ट्रपति भवन एवं विभिन्न अहम स्थानों के आसपास तैनात रहेंगे. शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली में श्री टियर



सिक्वियरिटी (तीन लेयर की) रहेगी।

समारोह में इन देशों के नेता

हो सकते हैं शामिल भारत ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामखेलावन को आमंत्रित किया है. नेपाल की पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे. दहल रविवार से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे।

नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है. 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद शुक्रवार (7 जून) को एनडीए

संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव पर एनडीए घटक दल के सभी नेताओं ने अपनी सहमति जताई।

एनडीए ने 292 सीटों पर दर्ज की जीत जिसमें बीजेपी की 240, इसके बाद मोदी ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार

इंडिया गठबंधन से अब दिल्ली हुई दूर....



परिवहन विशेष। एसडी सेटी।

नई दिल्ली। शुक्रवार को भाजपा नीत एनडीए गठबंधन ने संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून शाम 6:00 बजे तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल के नवनिर्वाचित सांसदों के बीच उपस्थित नरेंद्र मोदी को संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव भाजपा के राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया। प्रस्ताव का अनुमोदन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उसके बाद एनडीए के घटक दल टीडीपी के नेता चन्द्रबाबु नायडू द्वारा भी अनुमोदन कर सर्वसम्मति से पास किया गया। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी के गले लगाकर पैर छुए। शिव सेना के एकनाथ शिंदे, एएनजेपी के पासवान, समेत

तमाम घटक दल के नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। एनडीए घटक दलों का समर्थन मिलने के बाद नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो गया है।

दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने अब तक अपने पीएम का नाम तक तय ही नहीं कर पाए हैं। इस बीच गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से नाता तोड़कर लिया है। आप ने एलान कर दिया है कि उसका कांग्रेस से रिश्ता महज लोकसभा चुनाव तक था।

फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी एकला चलो पर अमल करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिव सेना उदव ठाकरे के नेता भी एनडीए में आने को तैयार है। जल्द ही वह भी इंडी गठबंधन को ओके बॉय बॉय टाटा करने जा रहे हैं। इसको देखते हुए जाहिर है कि इंडी गठबंधन का जोड़ खुल गया है। वह बिखरने के कगार पर है। इससे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन से अब धीरे-धीरे दिल्ली दूर होती जा रही है।

जल संरक्षण वास्तव में एक गंभीर मुद्दा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जल संरक्षण वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है, खासकर पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में। फरीदाबाद में कार धोने वाले गैराजों द्वारा पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एफएमडीए सीईओ के प्रयास सराहनीय हैं। हालाँकि, जैसा कि आपने बताया, व्यक्तियों द्वारा पानी के दुरुपयोग को संबोधित करना, जैसे कि गृहिणियाँ घर के रैप को साफ करना, भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए, एफएमडीए सीईओ निम्नलिखित कदमों पर विचार कर सकते हैं:

- कड़े विनियमन को लागू करना: ऐसे कानून बनाए जो घर के रैप धोने सहित गैर-आवश्यक गतिविधियों के

लिए पानी के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन विनियमों में उल्लंघन के लिए दंड शामिल होना चाहिए।

- जन जागरूकता अभियान: निवासियों को जल संरक्षण के महत्व और पानी की कबाँदी के प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करें। इसमें कार्यशालाएँ, सामुदायिक बैठकें और सूचनात्मक सामग्री शामिल हो सकती हैं।
- वैकल्पिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: जल-सघन सफाई के विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि झाड़ू लगाना या जल-कुशल सफाई विधियाँ और प्रौद्योगिकियाँ का उपयोग करना।
- जल उपयोग ऑडिट: आवासीय



क्षेत्रों में पानी के उपयोग की निगरानी करने और उच्च खपत वाली गतिविधियों की पहचान करने के लिए

- सामुदायिक भागीदारी: पड़ोस के समूह बनाकर संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करें जो जिम्मेदार जल उपयोग की निगरानी और प्रचार करते हैं।
- संरक्षण के लिए प्रोत्साहन: उन परिवारों के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करें जो जल-बचत उपायों को अपनाते हैं, जैसे कि पानी के बिल या मान्यता कार्यक्रमों पर छूट।
- नियामक उपायों को शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के साथ जोड़ें, एफएमडीए व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर पानी की कबाँदी को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, जिससे भविष्य के लिए स्थायी जल उपयोग सुनिश्चित हो सके।

सफदरजंग अस्पताल ने योग को चिकित्सा पद्धति में शामिल करने के लिए किया सेमिनार का आयोजन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRYN) के तहत सफदरजंग अस्पताल में योग और प्राकृतिक चिकित्सा ओपीडी और जीवनशैली हस्तक्षेप केंद्र ने रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए चिकित्सा पद्धति में योग को शामिल करना शीर्षक से एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

इस सेमिनार में योग, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान के क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने चिकित्सा पद्धति में योग को शामिल करने के बहुमुखी लाभों का पता लगाने के लिए एक साथ आयोजी। सुखिता जॉर्ज योग और प्राकृतिक चिकित्सा वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सक ने बताया कि इस कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के लगभग 85 चिकित्सा पेशेवरों ने भाग लिया, जिनमें डॉ. जयंती मणि अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, डॉ.



आर. पी. अरोड़ा एएमएस, डॉ. गौरव अरोड़ा एएमएस, एलोपैथी डॉक्टर, रेजिडेंट, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य सेवा प्रशासक और आयुष विभाग के डॉक्टर शामिल थे।

सेमिनार के मुख्य आकर्षण में शामिल है: योग के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभों पर साक्ष्य-आधारित अंतर्दृष्टि, सीसीआरवाईएन के निदेशक डॉ. राघवेंद्र राव जैसे प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई। चिकित्सा सेंट्रिस में योग के उपयोग को

और अधिक मान्य और विस्तारित करने के लिए शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के बीच सहयोगी अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा। र स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए स्वस्थ जीवन शैली अभ्यास और योगह पर एक व्यावहारिक सत्र, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बर्नआउट को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया, डॉ. अथिराय के.आर. द्वारा लिया गया। “बाई-ब्रेक” पहल का परिचय,

कर्मचारियों के बीच मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल के लिए डिज़ाइन किया गया एक छोटा, निर्देशित योग सत्र। CCryn के निदेशक डॉ. राघवेंद्र राव ने कहा, “चिकित्सा पद्धति में योग का एकीकरण स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों को लाभान्वित करता है।” “यह सेमिनार योग के वैज्ञानिक आधार और आधुनिक चिकित्सा में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को उजागर करने में महत्वपूर्ण रहा है।” सफदरजंग अस्पताल में योग और प्राकृतिक चिकित्सा ओपीडी और जीवनशैली हस्तक्षेप केंद्र शिक्षा, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जो व्यक्तियों और समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समग्र प्रथाओं को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने का प्रयास करता है।

क्या आप “कानून 30” और कानून “30 ए” के बारे में जानकारी रखते हैं ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। 130-A संविधान में निहित एक कानून है। इस कानून को संविधान में शामिल करने की कोशिश की गई तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा, रयह कानून हिन्दुओं के साथ विश्वासघात है, इसलिए अगर यह कानून संविधान में लाया गया, तो मैं इसके खिलाफ कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूँगा। आखिरकार सरदार पटेल की इच्छा के आगे घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं इस घटना के बाद कुछ ही महीनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अचानक मौत हो गई ? सरदार पटेल की मृत्यु के बाद इस कानून को संविधान में शामिल किया गया।

30-ए क्या है इस कानून के अनुसार – हिंदुओं को अपना रहिन्दू धर्म स्विचाने/पढ़ाने की अनुमति नहीं है।

र अधिनियम 30-ए उसे अनुमति या अधिकार नहीं देता है। हिन्दुओं को अपने निजी कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू धर्म पढ़ाना मना है। हिंदू धर्म सिखाने/पढ़ाने के लिए भारत देश में इस कानून के कारण स्कूल/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान शुरू नहीं हो सकते। एक्ट 30-ए के तहत पब्लिक स्कूलों या कॉलेजों में हिन्दू धर्म पढ़ाने की किसी को अनुमति नहीं है।

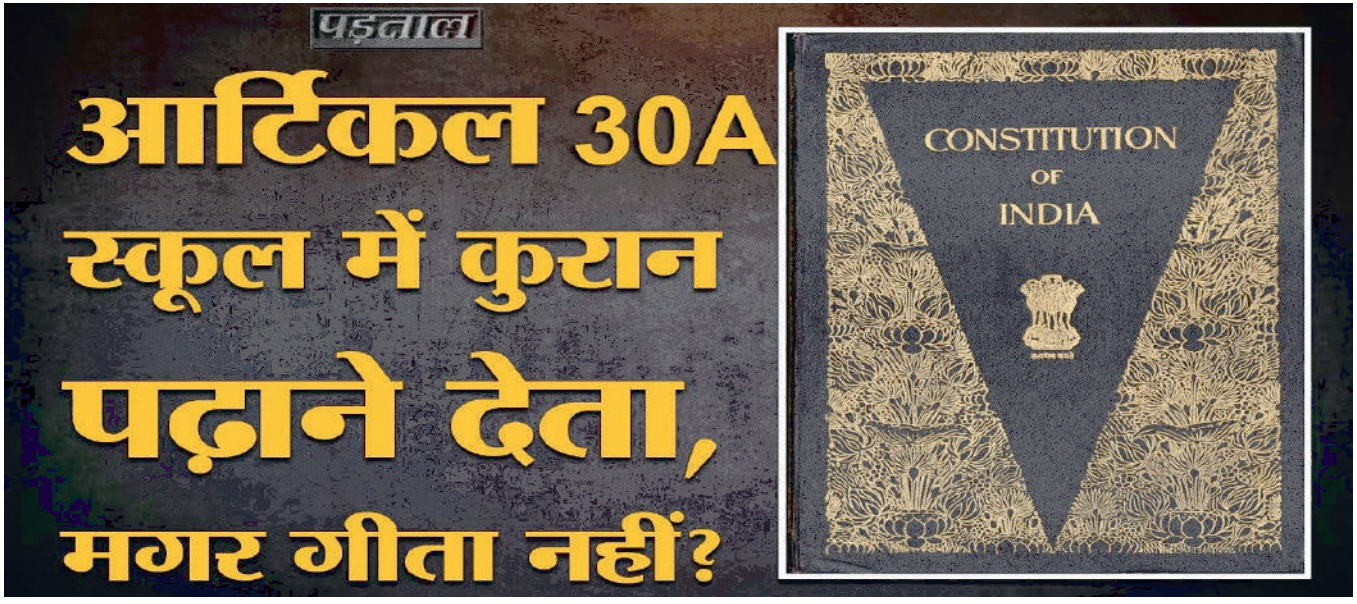
“कानून 30”। इस “कानून 30” के अनुसार मुसलमान, सिख और ईसाई अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए इस्लामी, सिख, ईसाई धार्मिक स्कूल शुरू कर सकते हैं।

मुसलमान, सिख और ईसाई अपना धर्म सिखा सकते हैं।

कानून 30 मुसलमानों को अपना 'मदरसा' शुरू करने का पूरा अधिकार और अनुमति देता है और संविधान का अनुच्छेद 30 ईसाइयों को अपने धार्मिक स्कूल और

कॉलेज स्थापित करने और पढ़ाने और सिखाने का पूरा अधिकार और अनुमति देता है। फ्री में अपने धर्म का प्रचार करो, इसका दूसरा कानूनी पहलू यह है कि हिन्दू मंदिरों का सारा पैसा और संपत्ति सरकार के विवेक पर छोड़ी जा सकती है, हिन्दू मंदिरों में हिंदू भक्तों द्वारा किए गए सभी धन और अन्य दान को राज्य के खजाने में ले जाया जा सकता है।

वहीं मुस्लिम और ईसाई मस्जिदों से दान और भिक्षा केवल ईसाई-मुस्लिम समुदाय के लिए दी जाती है। अधिनियम 30-ए और अधिनियम 30ए को लागू करने से हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ। यही कारण है आज हिन्दू लोक कथाओं तक सीमित है। हिन्दुओं को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। यह अनुच्छेद 30-ए के कारण है कि हम अपने देश में कहीं भी भगवद गीता नहीं पढ़ा सकते हैं।



निजी बदलावों से ही बदलेगा समाज

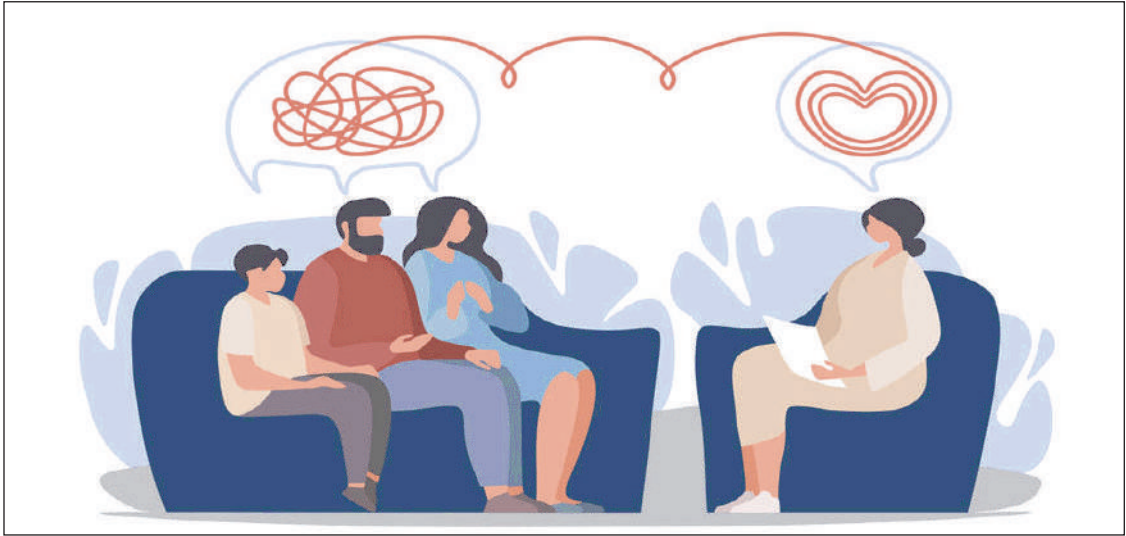


भारत डोगरा

व्यक्तिगत जीवन में समता का अर्थ यह है कि जितनी भी संपत्ति या आय हमारे पास हो, अपनी जरूरतों और जरूरी बचत को पूरा करने के बाद वह गरीबी कम करने के लिए या किसी इतने ही जरूरी सार्वजनिक हित के कार्य में खर्च होनी चाहिए। समता का एक अर्थ यह भी है कि अपने से कमजोर आर्थिक हैसियत वाले जितने भी लोग हमारे दैनिक जीवन में सम्पर्क में आएँ, उनसे हम न्यायसंगत व्यवहार करें।

जो हमारी कुंठाएँ हैं, दूसरों के प्रति संकीर्ण सोच है, उससे मुक्त होने का प्रयास कर, अपने आसपास एक खुला, मुक्त माहौल बनाना चाहिए। दूसरों का दुःख-दर्द कम करने, उन पर हावी न होने, सह अस्तित्व और सहयोग के सिद्धांत केवल नजदीकी लोगों से हमारे संबंधों पर लागू नहीं होते, यह प्रकृति से, प्रकृति के विभिन्न रूपों से, विभिन्न जीव-जंतुओं से भी हमारे संबंधों पर लागू होते हैं। प्रकृति की हरियाली को बढ़ाएं, मूक प्राणियों के दुःख-दर्द को कम करें, यह भी जीवन का एक बहुत सार्थक पक्ष है। आदर्श जीवन कुछ बहुत ख्याति प्राप्त या ऊंचे पदों पर पहुंचे लोगों की बपौती नहीं है। एक व्यक्ति, एक परिवार का सार्थक बदलाव भी दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयासों में उसकी महत्वपूर्ण देन है। निराशा के कारण हैं तो आशा की संभावनाएं भी हैं। निराशा के बादलों से निकल कर आशा के प्रकाश को फैलाना होगा और छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर व्यक्ति की इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिलहाल इतना हमारे नियंत्रण में जरूर है कि बिना कोई देर किए हम आदर्श जीवन जीएं।

सब जानते हैं कि समाज को बदलने की शुरुआत निजी जीवन के बदलावों से होती है, लेकिन आम तौर पर इस जानी-पहचानी अवधारणा को हम अनदेखा करते रहते हैं। जाहिर है, इसे बार-बार याद दिलाते रहने की जरूरत है। इस बार इस लेख में इसी विषय को खगालने की कोशिश करेंगे। समाज-सुधार की चर्चा तो कई स्तरों पर होती है, पर व्यक्तिगत जीवन में सुधार की चर्चा कम हो गई है। अब चर्चा व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की अधिक है। व्यक्तिगत सुधार या व्यक्ति के आदर्शों की नहीं, पर समाज तो बहुत से व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है और व्यक्तिगत जीवन में सुधार व आदर्श के महत्त्व के बिना समाज सुधार भी आगे बढ़ सकेगा, इसकी संभावना कम है। सवाल यह है कि आदर्श समाज की सोच के अनुरूप व्यक्तिगत जीवन जीना है तो उसकी अनिवार्य शर्तें क्या हैं। संभवतः सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारा जीवन सादगी और समता पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक जीवन में यह धारणा बहुत मान्यता प्राप्त कर चुकी है कि जितनी अधिक उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर सको, जीवन उतना ही बेहतर होगा, जितना वैभवकारी घर बना सको, उतना ही जीवन सार्थक होगा। दूसरी ओर सादगी की अवधारणा बताती है कि हम अपने व अपने परिवार के सदस्यों को कोई शारीरिक कष्ट



दिएं बिना अपनी जरूरतों को जितना कम रख सकें, जीवन की सार्थकता उतनी ही बढ़ती है। चूंकि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, एक परिवार और दूसरे परिवार की परिस्थितियों में बहुत अंतर हो सकता है, अतः सादगी का आदर्श सामने रखने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। बुनियादी बात हमारे सोच की है, जीवन मूल्यों की है। एक बार हमने इस सोच को ऐसा बना लिया कि सार्थकता उपभोक्ता वस्तुओं को बढ़ाने में नहीं, यथासंभव कम करने में है, तो हम सादगी के रास्ते पर आ चुके हैं।

व्यक्तिगत जीवन में समता का अर्थ यह है कि जितनी भी संपत्ति या आय हमारे पास हो, अपनी जरूरतों और जरूरी बचत को पूरा करने के बाद वह गरीबी कम करने के लिए या किसी इतने ही जरूरी सार्वजनिक हित के कार्य में खर्च होनी चाहिए। समता का एक अर्थ यह भी है कि अपने से कमजोर आर्थिक हैसियत वाले जितने भी लोग हमारे दैनिक जीवन में सम्पर्क में आएँ, उनसे हम न्यायसंगत व्यवहार करें। चाहे वे हमारे नियमित कर्मचारी हों या घरेलू कार्य में सहयोग करने वाले, रिश्ता चालक या कुली, उनके प्रति हमारा व्यवहार यही होना चाहिए कि उनसे जितना सहयोग हम अपनी सीमाओं के बीच कर सकते हैं, उतना अवश्य करें। ईमानदारी एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसकी चर्चा प्रायः होती है, पर ईमानदारी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी के साथ समता और सादगी के आदर्शों को भी जीवन में अपनाना जरूरी है। समता और सादगी के आदर्श आपस में बहुत नजदीकी तौर पर जुड़े हुए हैं। इन दोनों आदर्शों को अपनाने से जीवन

में बहुत-सी विकृतियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं, कई बेकार की बातों से समय बच जाता है और तरह-तरह के रचनात्मक और सार्थक कार्यों के लिए समय उपलब्ध होने लगता है। जो उपभोक्ता वस्तुएं समाज और पर्यावरण के स्तर पर हानिकारक सिद्ध हो चुकी हैं, उनसे दूर रहना आवश्यक है। तंबाकू, शराब, अन्य तरह के नशीले पदार्थ, दुव्यसन व ऐय्याशो की सामग्री का किसी भी आदर्श जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए और कम से कम अपनी कमजोरी को छोड़ने की इच्छा जरूरत होनी चाहिए। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि आदर्श व्यक्तिगत जीवन में किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग के प्रति भेदभाव या नफरत की जगह नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जीवन इन सभी तरह के भेदभावों और उनसे उत्पन्न कुंठाओं और विकृतियों से मुक्त होना चाहिए। आदर्श जीवन के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, इसकी तो बहुत लंबी सूची तैयार की जा सकती है, पर यदि हम एक मूल बात को पकड़ना चाहते हैं तो वह यह है कि हम दूसरों को दुःख-दर्द न दें, अपितु जहां तक संभव हो, जितना अवसर हमें मिल सके, हम दूसरों का दुःख-दर्द कम करने का ही प्रयास करें।

ईमानदारी से अपनी आजीविका तो हमें कमाना ही है, अपनी व अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी करनी हैं, यह जिम्मेदारी निभाते हुए जितना हमसे बन सके, हम दूसरों का दुःख-दर्द कम कर सकते हैं, तो वह प्रयास हम जरूर करें, उससे पीछे न हटें। अपने-अपने संबंधों में प्रयास और सद्भावना होने के बावजूद प्रायः हम रिश्तों में हावी होने, अपनी हस्ती स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

इस कारण नाहक बहुत दुःख-दर्द उत्पन्न होता है। नजदीकी मानवीय संबंधों को एक-दूसरे पर हावी होने के स्थान पर 'हमारी भी जय हो, तुम्हारी भी जय हो' के सिद्धांत पर जीना चाहिए। जो हमारी कुंठाएं हैं, दूसरों के प्रति संकीर्ण सोच पर हानिकारक सिद्ध हो चुकी हैं, उनसे दूर रहना आसपास एक खुला, मुक्त माहौल बनाना चाहिए।

दूसरों का दुःख-दर्द कम करने, उन पर हावी न होने, सह अस्तित्व और सहयोग के सिद्धांत केवल नजदीकी लोगों से हमारे संबंधों पर लागू नहीं होते, यह प्रकृति से, प्रकृति के विभिन्न रूपों से, विभिन्न जीव-जन्तुओं से भी हमारे संबंधों पर लागू होते हैं। प्रकृति की हरियाली को बढ़ाएं, मूक प्राणियों के दुःख-दर्द को कम करें, यह भी जीवन का एक बहुत सार्थक पक्ष है। आदर्श जीवन कुछ बहुत ख्याति गुणों की आवश्यकता है, इसकी तो बहुत लंबी सूची तैयार की जा सकती है, पर यदि हम एक मूल बात को पकड़ना चाहते हैं तो वह यह है कि हम दूसरों को दुःख-दर्द न दें, अपितु जहां तक संभव हो, जितना अवसर हमें मिल सके, हम दूसरों का दुःख-दर्द कम करने का ही प्रयास करें।

ईमानदारी से अपनी आजीविका तो हमें कमाना ही है, अपनी व अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी करनी हैं, यह जिम्मेदारी निभाते हुए जितना हमसे बन सके, हम दूसरों का दुःख-दर्द कम कर सकते हैं, तो वह प्रयास हम जरूर करें, उससे पीछे न हटें। अपने-अपने संबंधों में प्रयास और सद्भावना होने के बावजूद प्रायः हम रिश्तों में हावी होने, अपनी हस्ती स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

संपादक की कलम से भाजपा से क्यों रूठे राम?

अयोध्या के राम मंदिर ने भाजपा की चुनावी मदद क्यों नहीं की? राम मंदिर आम चुनाव, 2024 का प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? क्या प्रभु राम भाजपा से रूठ गए हैं? श्रीराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी, 2024 को इस मकसद से तय किया गया था कि राम मंदिर चुनावों तक एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा और उसके मद्देनजर ध्रुवीकरण होगा। भाजपा को चुनावी लाभ होगा। राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन सतही तौर पर किसी ने भी किया हो, लेकिन उसके सूत्रधार, प्रथम यजमान प्रधानमंत्री मोदी ही थे। फोकस उन्हीं पर था। एक रामभक्त की तरह, पैदल चलते हुए और आरती की थाली लेकर, प्रधानमंत्री ही राम-प्रतिमा तक गए थे। पूजा-पाठ की तमाम विधियां निभाई थीं। उस आयोजन के बाद बृथ स्तर के काडर को निर्देश दिए गए थे कि भक्तों को अयोध्या तक लाया जाए, ताकि वे सहजता से प्रभु राम के दर्शन कर सकें। अयोध्या के पुनरोत्थान, विकास और विस्तार पर भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने 70,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिया था। अयोध्या का चेहरा ही बदल दिया, लेकिन अयोध्या के मतदाताओं ने भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को ही 54,000 से अधिक मतों से हरा दिया। लल्लू सिंह को 2014 और 2019 में लगातार दो बार अयोध्या (फैजाबाद) का सांसद चुना गया था। यही नहीं, 26 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव हार गए। उनमें स्मृति ईरानी, महेंद्र पांडेय, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्रा, भानुप्रताप वर्मा आदि केंद्रीय मंत्री उप्र से ही सांसद चुनकर आए थे। इस बार अयोध्या के इंद-गिर्द 4-5 अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी भाजपा को पराजित किया गया। भाजपा का वोट प्रतिशत 50 फीसदी से घटकर 41 फीसदी हो गया और वह 29 सीट नीचे फिसल गई, जबकि सपा का वोट प्रतिशत 18.11 फीसदी से उछल कर 33.5 फीसदी हो गया। सपा की इस चुनाव में ही 32 सीटें बढ़ गईं। कांग्रेस के हिस्से भी 6 सांसद आए गए, जिसके मात्र 2 विधायक हैं। प्रभु राम भाजपा से एकदम क्यों रूठ गए? विशेषज्ञ मान रहे थे कि

भाजपा 80 में से 70 से अधिक सीटें तो जीत सकती है। उप्र के कारण ही भाजपा लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। सवाल है कि क्या संविधान बदलने, लोकतंत्र खत्म करने, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने सरीखे भ्रामक मुद्दे इतने प्रभावशाली साबित हुए कि रामभक्तों ने भी भाजपा को खारिज कर दिया और उस पार्टी को वोट दिए, जिसके मुख्यमंत्री ने रामभक्तों, कारसेवकों पर गालियों की बौछार करवा उनको हत्याएं कराई थीं। अयोध्या (फैजाबाद) के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने भी बयान दिया था कि भाजपा को 400 सीटें इसलिए चाहिए, ताकि संविधान में अपेक्षित बदलाव किए जा सकें। विपक्षी गठबंधन ' इंडिया ' ने इसकी गलत व्याख्या की कि भाजपा संविधान को ही बदलना चाहती है। संविधान बदल जाएगा, तो आरक्षण की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। इसका जबरदस्त असर दलितों, आदिवासियों, ओबीसी पर पड़ा और उन्होंने रामभक्त होते हुए भी भाजपा के खिलाफ लामबंद होकर मतदान किया। मतों का ध्रुवीकरण ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी व्യാराणसी सीट से 1.52 लाख से कुछ ज्यादा मतों से ही जीते।

2019 में वह चार लाख से अधिक मतों से जीते थे। प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव के दौरान जनता को आश्चस्त करते रहे कि अब बाबा अंबेडकर भी संविधान को बदल नहीं सकते। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आगे भी रहेगा, लेकिन आरक्षित जमात में विपक्ष के आरोपों का खूब असर हुआ। अयोध्या के कुछ स्थानीय मुद्दे भी रहे होंगे, अधिग्रहण की गई जमीनों के पर्याप्त मुआवजे नहीं दिए गए होंगे, नतीजतन प्रतिक्रिया भाजपा के खिलाफ गई और चुनाव-परिणाम सामने हैं। फिर भी अकेली भाजपा ने लोकसभा की 240 सीटें जीती हैं, जो अभूतपूर्व जनादेश है। 1985 में देश ने 404 सीटों का जो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया था, उसके बाद 232 से अधिक कोई भी पार्टी जीत नहीं पाई है। अयोध्या भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमि है, बेशक पार्टी इसे ' आस्था ' मानती रहे।

चर्चा

छोटा हिमाचल, सबक बड़े-4

हिमाचल के समग्र राजनीतिक परिदृश्य को चुनाव परिणामों के बाद तय करना होगा कि जनता ने सुना क्या और सुनाया क्या। जनता ने अपने अधिकारों, सियासत के नारों, सरकार के वादों और केंद्र पर निर्भर पुरस्कारों को सुना है। इसी जनता ने अपने नुमाइंदों के मार्फत हिमाचल व केंद्र में आने वाली सरकार को बहुत कुछ सुनाया भी है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पांचवीं बार अनुराग ठाकुर की ताजपोशी के आगे बाकी सांसद फीके साबित हुए हैं। चाहे शांता कुमार हो या किशन कपूर, इनके दौरे से कहीं आगे अनुराग ठाकुर निकले हैं तो समूचे प्रदेश के लिए सोचने वाला एक अदद केंद्रीय मंत्री चाहिए। देशक अनुराग ठाकुर का पद और कद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर गया, लेकिन उन्हें पूरे प्रदेश का ' नया नेता ' तो रेले-हवाई विस्तार के अलावा पर्यटन, खेल पर्यटन, धार्मिक पर्यटन व औद्योगिक विस्तार की परियोजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर भी देखना होगा। जरूरी नहीं कि रेल विस्तार करते हुए केवल हमीरपुर ट्रेन पर चढ़ा जाए। आसानी से अगर अंब-अंदौरा तक पहुंची ट्रेन को नब्बे डिग्री उत्तर की ओर बढ़ाया जाए तो केंद्रीय हिमाचल में रेल विस्तार ज्वालामुखी के मार्फत, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व मंडी तक पहुंचेगा। इसी तरह नर्मदाताल से मुबारकपुर तक प्रस्तावित फोरलेन परियोजना के ताले खोलने पड़ेंगे। आश्चर्य यह कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी वह प्रदेश के खेल ढांचे तथा रेडियो-टीवी विस्तार में चाँछित नहीं कर पाए। नई सरकार को संभावना में, भाजपा की सत्ता में उनका स्थान निस्संदेह तरक्की पर रहेगा, लेकिन प्रदेश की निगाह में उनका रुतबा इस घाटी में व्यापकता देखना चाहता है। यह चुनौती बाकी सांसदों के लिए भी रहेगी कि वे अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में कुछ न कुछ करके दिखाएं। अगर चारों सांसद प्रदेश के समग्र विकास में सोचें, विशेष आर्थिक याररेवे पैकेज की मांग करें और पंजाब पुनर्गठन की बंद फाइलों से हिमाचल के हितों को मुक्त कराएं, तो सी फ्रीस्टैंड में अपने-अपने विमर्श, तर्क और तंज लेकर एक दूसरे को कोस रहे होंगे, लेकिन याद रखना होगा कि हिमाचल एक संसाधन विहीन राज्य है जिसे आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास दिलाने के लिए सांसदों, विधायकों और राज्य सरकार को एक साथ प्रयास करना होगा।

प्रताप सिंह पटियाल

लोकतंत्र के पर्व में शिकस्त व जीत का सिलसिला जारी रहेगा, मगर अहम पहलू यह है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए। देश की सियासत को जनता का जनादेश पूरी अकीदत से स्वीकार करना होगा।

मौजूदा वक्त में मुल्क की सियासत जश्न-ए-मसरत में मसरूर है। देश की फिजाओं में भी सियासी तरल्युम की धुन महसूस की जा सकती है। देश के करोड़ों मतदाताओं ने अपने बेशकीमती वोट का ताकत से मैदान-ए-सियासत में किस्मत आजमा रहे सियासी रहनुमाओं को जम्हूरियत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा कर लोकतंत्र की मजबूती का एक और सुनहरा मजमून लिख दिया। सियासत के कई मुनाजिर सियासी बज्म में चुनावी जीत का श्रेय लेने में लगे हैं, जबकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। हैरत यह भी है कि मतदाताओं ने अलगाववाद की हिमायत करने वाले कुछ सियासी रहनुमाओं को भी देश की संसद में भेज दिया है। चुनावी रैलियों से लेकर जनसम्पर्क व रोड शो तक सियासी मीडिया तक चुनावों का प्रचार हुआ। सियासी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके चुनावों में सियासी विरासत को बचाने की जद्दोजहद भी जारी थी, मगर मतदाताओं के खामोश फैसले ने देश की सियासत को चौंका दिया है। एग्जिट पोल को लेकर सियासत के ज्योतिषाचार्यों के दावे धराशायी हो गए। हालांकि देश में एक बार फिर गठबंधन की सियासत का दौर शुरू हो गया है। कहर बरपाती गर्मी के बीच लोग ने मतदान केंद्रों की कतारों में खड़े होकर मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के प्रति अपना फर्ज अदा कर दिया। यह दौर बात है कि अगले पांच वर्षों तक जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का

पालन पूरी शिद्दत से करेंगे। चुनावों के बाद आम लोगों को अपने सियासी रहनुमां के दीदार दुर्लभ हो जाते हैं। देश का हर चुनाव अपने पीछे कई यादें छोड़ जाता है।

मौजूदा लोकसभा चुनाव में लोगों में मतदान के प्रति उत्साह का माहौल कम था। कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, मगर आरोप-प्रत्यारोप के भयानक दौर में शराफत व अदब की हद्द को तोड़ने वाली भाषा के चलते सियासत की दर्जा-ए-हरारत बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। गुफ्तगू के दौरान लफ्जों का इस्तेमाल व बात करने का सलीका किसी भी इनसान की तरबियत व परवरिश का बहतरीन सबूत होता है। जहरीले लफ्जों से उपजे गहरे जख्म दशकों तक नहीं भरते। इंतखाबी तश्हीर के दौरान सियासी रहनुमाओं की जुबान से निकले तीरनुमां लफ्जों ने मुल्क की सियासत को काफी हद तक मफलूज कर दिया है। सियासत के किरदार का अनांखा अंदाज है कि मुल्क में सियासी रहनुमाओं को ही दानिश्वर माना जाता है। देश की अफसरशाही व नौकरशाही तथा तमाम व्यवस्थाएं सियासत के आगे नतमस्तक रहती हैं। आम लोग ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों से ही अपेक्षा रखते हैं। भोली-भाली विरासत के लोग सियासतदारों के आशवासनों पर अक्सर विश्वास कर लेते हैं, जबकि सियासत की कथनी और करनी में फर्क होता है।

सियासत एक ऐसा पेशा है जिसमें अपने सियासी दुर्ग फतह करने के लिए सियासी रहनुमाओं के झूठ बोलने पर, मौके की नजाकत को भांपकर जाति-मजहब का कार्ड खेलना, वोट बैंक बचाने के लिए जराफत परे अंदाज में लोकलुभावन वादों की बिसात बिछाना तथा चुनावी प्रचार के दौरान की गई घोषणाओं से मुकरने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। इसीलिए सियासत के मिजाज से कभी सदाकत की महक नहीं आती। सियासी रहनुमाओं के किरदार में



मोहिब्ब-ए-वतन का अक्स नहीं दिखाई देता। इंतखाबी तश्हीर में हिकारत परे अल्फाज व बड़बोली भाषणबाजी के आगे निर्वाचन आयोग भी बेवस हो चुका है। लेकिन सत्ता की दहलीज पर पहुंचने की होड़ में जनसेलाब को अर्मायादित भाषा से उकसाना तथा लोगों के सज्जात आदत करने की कारकदंगी मतदाताओं के साथ पूरे जम्हूरी निजाम को लौहीन है। चुनाव आयोग को इस विषय पर संज्ञान लेना होगा। नवगठित मरकजी हुकूमत से देश के करोड़ों लोगों को उम्मीदें रगेंगी, मगर सबसे ज्यादा उम्मीद युवा वर्ग को है। कुछ दर्द इनसान का सुख-चैन छीन कर उसे खामोशी व तन्हाई के आलम में जीने को मजबूर कर देते हैं। बेरोजगारी के सैलाब में फंस चुके युवा वर्ग का हाल कुछ ऐसा ही है। लाइलाज हो चुकी बेरोजगारी के अजाब से युवा वर्ग मानसिक तौर पर मामूर हो चुका है। हर वर्ष हजारों युवा जमीन-जायदाद गिरवी रखकर रोजगार की तलाश में डंडी रूट के जरिए विदेश

जाते हैं तथा वहां की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। विदेशों में पढ़ाई करने वाले भारतीय मूल के छात्रों व रोजगार में लगे युवाओं पर नस्लीय हमले व हत्याएं आम बात हो चुकी है। देश में नशा माफिया के राडार पर भी बेरोजगार युवा हैं। नशाखोरी के मामलों में सलाखों के पीछे भी ज्यादातर युवा वर्ग है। जम्हूरी निजाम को लौहीन है। चुनाव आयोग को इस विषय पर संज्ञान लेना होगा। नवगठित मरकजी हुकूमत से देश के करोड़ों लोगों को उम्मीदें रगेंगी, मगर सबसे ज्यादा उम्मीद युवा वर्ग को है। कुछ दर्द इनसान का सुख-चैन छीन कर उसे खामोशी व तन्हाई के आलम में जीने को मजबूर कर देते हैं। बेरोजगारी के सैलाब में फंस चुके युवा वर्ग का हाल कुछ ऐसा ही है। लाइलाज हो चुकी बेरोजगारी के अजाब से युवा वर्ग मानसिक तौर पर मामूर हो चुका है। हर वर्ष हजारों युवा जमीन-जायदाद गिरवी रखकर रोजगार की तलाश में डंडी रूट के जरिए विदेश

जाते हैं तथा वहां की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। विदेशों में पढ़ाई करने वाले भारतीय मूल के छात्रों व रोजगार में लगे युवाओं पर नस्लीय हमले व हत्याएं आम बात हो चुकी है। देश में नशा माफिया के राडार पर भी बेरोजगार युवा हैं। नशाखोरी के मामलों में सलाखों के पीछे भी ज्यादातर युवा वर्ग है। जम्हूरी निजाम को लौहीन है। चुनाव आयोग को इस विषय पर संज्ञान लेना होगा। नवगठित मरकजी हुकूमत से देश के करोड़ों लोगों को उम्मीदें रगेंगी, मगर सबसे ज्यादा उम्मीद युवा वर्ग को है। कुछ दर्द इनसान का सुख-चैन छीन कर उसे खामोशी व तन्हाई के आलम में जीने को मजबूर कर देते हैं। बेरोजगारी के सैलाब में फंस चुके युवा वर्ग का हाल कुछ ऐसा ही है। लाइलाज हो चुकी बेरोजगारी के अजाब से युवा वर्ग मानसिक तौर पर मामूर हो चुका है। हर वर्ष हजारों युवा जमीन-जायदाद गिरवी रखकर रोजगार की तलाश में डंडी रूट के जरिए विदेश

भितरघात पर मंथन

बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में मंथन हो रहा है। जीत पर भी मंथन हो रहा है और हार पर भी मंथन हो रहा है। इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैठक के एजेंडे में भितरघात पर मंथन भी शामिल है। भितरघात जिन-जिन लोगों ने किया था, वे भी बड़ी गंभीरता के साथ इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में जब भितरघात पर चर्चा हो रही है तो ऐसे लोग बढ़-चढ़कर अपने-अपने सुझाव रख रहे हैं ताकि भविष्य में भितरघात न हो। ऐसे लोगों का मानना है कि भितरघात पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। भितरघात रोकने के लिए कड़ी गाइडलाइन दी जानी चाहिए, ऐसा सुझाव भी मंथन बैठक में दिया जा रहा है। बैठक में मिष्ठान भी वितरित किया जा रहा है क्योंकि जीत भी हुई है और जीत पर चर्चा मीठे मुंह से

की जानी चाहिए। लेकिन कड़वा कुछ नहीं बांटा जा रहा क्योंकि हार भी हुई है। इसलिए मिष्ठान खाते हुए रिफ्रिंक ड्रिंक्स चूट रहे जा रहे हैं। बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। पिछले तीन घंटे से मंथन चल रहा है। इसलिए चर्चा रहा है क्योंकि मंथन की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जानी है। फिर हाईकमान इस रिपोर्ट पर मंथन करेगा स जिसके लिए अलग से बैठक होगी और वह हाईकमान के लेवल पर होगी। यह बैठक स्थानीय लेवल पर हो रही है क्योंकि भितरघात भी स्थानीय लेवल पर हुआ है। इसलिए स्थानीय लेवल के नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने बृथ की रिपोर्ट और सुझाव लेकर बैठक में आए हुए हैं। बीच में दो-तीन बार लाइट चली जाती है तो पंखे-कूलर बंद हो जाते हैं। मंथन थम जाता है।

मंथन बैठक में शामिल लोग पसीने से तर-बतर हो जाते हैं। बैठक में शामिल एक शख्स कहता है कि हमारी मंथन बैठक को डिस्टर्ब करने के लिए सरकार की ओर से जानबूझकर लाइट गुल करवाई गई है। इसलिए इस बैठक में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। दूसरा शख्स बैठक में खड़ा होकर कहता है कि इस बैठक से पहले जेनेरेटर का इंतजाम होना चाहिए था ताकि लाइट जाए ही नहीं। मंथन बैठक में उपस्थित तीसरा शख्स उठकर कहता है कि हम इस बैठक में बिजली व्यवस्था पर चर्चा करने नहीं आए हैं, बल्कि जीत-हार और भितरघात पर मंथन करने आए हैं, इसलिए विषय से भटका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भटके हुए लोग ही पार्टी को भटका देते हैं और देश में लोकतंत्र भटक जाता है। एक और शख्स बैठक में

उठकर कहता है कि हमारी पार्टी में भी कुछ भटके हुए लोग आए हैं जो इस बैठक में भी उपस्थित नहीं हैं। इन लोगों की वजह से पार्टी में काफी भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम अपनी दिशा और दशा भटक रहे हैं। एक और शख्स इसी बीच अपनी जगह से उठकर कहता है कि बाहर मीडिया वाले भी बैठे हैं और बैठक खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें खबर का मसाला मिल सके। अगर यह बैठक विषय से ही भटक गई तो हम भटके हुए लोग मीडिया को क्या बताएंगे? मीडिया ने तो पहले ही देश को भटका रखा है। एग्जिट पोल के बहाने दो दिन तक जनता को भटका कर रखा। जब रिजल्ट निकला तो हम आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गए। इसलिए अटक गए क्योंकि हम भटक गए। भटक हुए लोग लोकतंत्र को कोई दिशा

नहीं दे सकते। इसलिए इस बैठक में अटकने और भटकने पर मंथन होगा। पार्टी की जीत-हार और भितरघात पर बाद में मंथन किया जा सकता है। हाईकमान को बाद में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। एक सदस्य उठकर कहता है कि हाईकमान ने भी यह मंथन रिपोर्ट अंजता: डस्टबिन में डालनी है, इसलिए बैठक में ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अभी यह चर्चा चल ही रही होती है कि इसी बीच लाइट आ जाती है। अब लाइट में मंथन शुरू हो जाता है। बात घूम फिर कर फिर भितरघात पर आ जाती है। भविष्य में नुकसान न हो, इस बारे कोई ठोस नीति बनाने की बात बैठक में उठती है। नीति से ही राजनीति चलती है, यह निष्कर्ष निकलता है।

गुरमीत बेदी



वृंदावन: धाम है, पर्यटन नगरी नहीं - एक अपील : अंकुर



वृंदावन, श्रीकृष्ण की पावन भूमि, एक धाम है, पर्यटन नगरी नहीं। यहाँ की कुंज गलियों में आपके बड़े वाहनों का समेत पाना मुश्किल हो जाता है। जब आप परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिंग की व्यवस्था भी कम पड़ जाती है। अतः, जो लोग वृंदावन आते हैं, उनसे विनम्र अपील है कि वे यहाँ के नियमों और अनुशासन का पालन करें।

संयम और धैर्य का परिचय दें
वृंदावन की गलियाँ संकरी हैं और यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। ऐसे में, बड़े वाहनों का प्रवेश कठिनाई पैदा करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि अपने वाहन को धीरे चलाएँ और हॉर्न का कम से कम प्रयोग करें। अक्सर देखा गया है कि परिक्रमा मार्ग पर चलते समय श्रद्धालु वाहनों की चपेट में आ जाते हैं या उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है।

पैदल यात्रा को प्राथमिकता दें
यदि आपको वृंदावन की यात्रा करनी है, तो पैदल चलने की आदत डालें। इससे न

केवल आपका तनाव कम होगा, बल्कि यातायात का भार भी कम होगा। वृंदावन की संकरी गलियों में पैदल चलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। इससे न केवल आपकी सेहत में सुधार होगा, बल्कि आप यहाँ की संस्कृति और वातावरण का भी पूर्ण आनंद ले सकेंगे।

यातायात व्यवस्था में सुधार
अक्सर देखा जाता है कि लोगों से ज्यादा तो ई-रिक्शा और गाड़ियाँ सड़क को जाम कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी सड़क को खाली कराने में ही लग जाती है। इससे बचने के लिए, यह आवश्यक है कि आप यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का सम्मान करें।

वृंदावन एक पावन धाम है, यहाँ की गलियाँ संकरी और पारंपरिक हैं। इसे पर्यटक स्थल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक धार्मिक धाम के रूप में सम्मान देना चाहिए। यदि आप वृंदावन आते हैं, तो कृपया संयम का परिचय दें, पैदल यात्रा को प्राथमिकता दें, और यातायात के नियमों का



पालन करें। इससे न केवल आपकी यात्रा सुखद होगी, बल्कि वृंदावन की पवित्रता और सौंदर्य भी बना रहेगा।

आइए, हम सब मिलकर वृंदावन की पवित्रता और सुंदरता को बनाए रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।

वृंदावन धाम की सुरक्षा और स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है।

indiangreenbuddy@gmail.com

रामोजी राव के निधन पर कई सितारों ने जताया शोक, चिरंजीवी और एसएस राजामौली ने भी दी श्रद्धांजलि

मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती रामोजी राव के निधन पर फिल्म अभिनेता और पद्म विभूषण से सम्मानित चिरंजीवी ने शनिवार को शोक व्यक्त किया। मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती एवं खबरों और मनोरंजन की दुनिया में व्यापक बदलाव लाने वाले रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव का शनिवार सुबह यहाँ एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे।

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद। मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती रामोजी राव के निधन पर फिल्म अभिनेता और पद्म विभूषण से सम्मानित चिरंजीवी ने शनिवार को शोक व्यक्त किया। मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती एवं खबरों और मनोरंजन की दुनिया में व्यापक बदलाव लाने वाले रामोजी समूह के अध्यक्ष रामोजी राव का शनिवार सुबह यहाँ एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे।

रामोजी राव के निधन पर चिरंजीवी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा, हमुझे पूरा विश्वास है कि उनके उत्तराधिकारी उनके सपने को आगे ले जाएंगे और उसे पूरा करेंगे। सभी ने उनमें एक महान व्यक्ति देखा होगा, लेकिन मैंने उनमें एक छोटा बच्चा देखा है।"

उन्होंने कहा, 2009 में मैं उनसे अक्सर मिलता था और प्रजा राज्यम पार्टी के लिए उनकी सलाह लेता था... वे अपने विचारों को अलग-अलग रंगों की स्थाही से डायरी में लिखते थे। वे हमेशा सोचते थे कि समाज के लिए आगे क्या करना है... यह न केवल उनके परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, बल्कि तेलुगु लोगों ने एक महान व्यक्ति और महान शक्ति खो दी है। वे जहाँ भी होंगे, हमारे साथ रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।



रामोजी राव के निधन पर रजनीकांत, चिरंजीवी, अल्लु अर्जुन, राम चरण और जूनियर एनटीआर समेत सिनेमा जगत की कई हस्तियों ने शनिवार को शोक व्यक्त किया। रामोजी राव ने समाचार पत्र 'ईनाडु' और ईटीवी चैनल समूह की शुरुआत करके अविभाजित आंध्र प्रदेश में मीडिया जगत में क्रांतिकारी बदलाव किया था। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

रजनीकांत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में राव को अपना मार्गदर्शक और शुभचिंतक बताते हुए कहा कि वह उनके निधन से "बहुत दुखी" है।

उन्होंने कहा, "पत्रकारिता और सिनेमा में इतिहास रचने वाले और राजनीति में महान 'किंगमेकर'। वे मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"

चिरंजीवी ने 'एक्स' पर एक भावुक संदेश पोस्ट करते हुए कहा कि रामोजी राव एक पहाड़ की तरह थे जो कभी किसी के सामने नहीं झुके। अल्लु अर्जुन ने कहा कि रामोजी राव एक "अग्रणी और प्रेरणादायक दूरदर्शी" थे और मीडिया दिग्गज के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है।

रामोजी फिल्म सिटी (आरएफसी) को 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में हजारों फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें एसएस राजामौली की दो भाग वाली ब्लॉकबस्टर 'बाहुबली' भी शामिल है। 'बाहुबली' और 'आरआरआर' के निर्देशक फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने कहा कि राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया जाना चाहिए।

अभी भी हिंसा में झुलस रहा मणिपुर! उग्रवादियों ने दो पुलिस चौकियों समेत 70 घर फूँके

मणिपुर के जिरिबाम जिले में उग्रवादियों ने शनिवार को एक समुदाय के 70 से अधिक घर जला दिए। उग्रवादियों ने दो पुलिस चौकियों वन विभाग के कार्यालय में भी आग लगा दी। हिंसा के बाद जिरिबाम के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षाकर्मियों की सहायता के लिए 70 से अधिक राज्य पुलिस कमांडो की टुकड़ी को इंग्फाल से जिरिबाम भेजा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग मैसेयी समुदाय के 239 लोगों को शुक्रवार को जिले के खेल परिसर में बनाए गए राहत शिविर में ले जाया गया है। इन्हें ज्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं।

दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षाकर्मियों की सहायता के लिए 70 से अधिक राज्य पुलिस कमांडो की टुकड़ी को इंग्फाल से जिरिबाम भेजा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि लगभग मैसेयी समुदाय के 239 लोगों को शुक्रवार को जिले के खेल परिसर में बनाए गए राहत शिविर में ले जाया गया है। इन्हें ज्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं।

वन विभाग के गोआखाल कार्यालय में भी आगजनी

वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उग्रवादियों ने लमताई खुनी, डिबोंग खुनी, नुनखाल और बेगरा गांवों में 70 से अधिक घरों को आग लगा दी। शनिवार सुबह उग्रवादियों ने जिरिमुख

और चोको बेकरा की पुलिस चौकियों और वन विभाग के गोआखाल कार्यालय में भी आगजनी। आगजनी के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने जिरिबाम के एसपी ए. घनश्याम शर्मा को मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के अतिरिक्त निदेशक के पद पर तबादला कर दिया।

उग्रवादियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के बाद भड़की हिंसा

एम. प्रदीप सिंह जो पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जिरिबाम जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उग्रवादियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के बाद हिंसा भड़की है। गुरुवार रात जिरिबाम में सोडबाम सरतकुमार सिंह का शव मिला था। शव पर जखम के कई निशान थे। इसके बाद

स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। जिरिबाम और आसपास के तामेंगलों जिलों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।

सांसद ने लोगों के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया

इस बीच भीतरी मणिपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अंगोमका बिमोल अकोईजाम ने कहा, राज्य सरकार से जिरिबाम जिले के लोगों के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया है। पिछले वर्ष मई से मणिपुर हिंसा से झुलस रहा है, लेकिन जिरिबाम अब तक जातीय संघर्ष से अप्रभावित रहा था। मणिपुर में मैसेयी और कुकी लोगों के बीच जातीय संघर्ष के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

भारतीय सेना के कंधे मजबूत करने के लिए मिले नए 473 युवा सैन्य अधिकारी, परेड में उत्तराखंड के रुतबा कायम

देश के नए सैन्य अधिकारी सीमा की रक्षा को तैयार हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 355 युवा अधिकारी मिले। इसके अलावा मित्र देशों के 39 कैडेट भी अकादमी से कड़ा प्रशिक्षण लेकर अपनी-अपनी सेना का हिस्सा बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुवेंद्र कुमार ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी ली।

नई दिल्ली। देश के नए सैन्य अधिकारी सीमा की रक्षा को तैयार हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 355 युवा अधिकारी मिले। इसके अलावा मित्र देशों के 39 कैडेट भी अकादमी से कड़ा प्रशिक्षण लेकर अपनी-अपनी सेना का हिस्सा बने हैं। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुवेंद्र कुमार ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी ली। इस बार भी परेड में उत्तराखंड का रुतबा कायम रहा।

पासिंग आउट कोर्स के लिए मिलने वाले पुरस्कारों में तीन उत्तराखंड के कैडेट के नाम रहे। वहीं, बिहार ओटीए में भी पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना व असम रायफल को मिले 118 अधिकारी मिले।

चेतवुड भवन के सामने डिल स्क्वॉयर पर हुई पासिंग आउट परेड
पासिंग आउट परेड भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक चेतवुड भवन के सामने डिल स्क्वॉयर पर हुई। सुबह

6 बजकर 47 मिनट पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती ताने कश के भावी कर्णधार असोमहिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाते हुए परेड के लिए पहुंचे। कैडेट ने शानदार मार्चपास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। निरीक्षण अधिकारी ने इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट को सम्मानित किया।

आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिये पुष्प वर्षा हुई

युवा सैन्य अधिकारी जब आंतिम पाग भर रहे थे तो आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिये उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। पास आउट बैच में शामिल देश-विदेश के 394 कैडेट परेड के बाद पीपिंग व ओथ सेरेमनी का हिस्सा बने, फिर अकादमी के निजाम पवेलियन में कसम परेड के बाद पहला कदम पार कर सैन्य अधिकारी बन गए। इनमें 355 युवा अधिकारी भारतीय थलसेना को मिले।

तकनीकी प्रगति के दौर में बदला लड़ाई का परिदृश्य

नव सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुवेंद्र कुमार ने कहा कि प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, साइबर, सूचना क्षेत्र और पारंपरिक उपकरणों की क्षमता में प्रगति से युद्ध का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। यह अधिक जटिल, संघर्षपूर्ण और घातक है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह कहावत भी याद रखें कि मशीनों के पीछे का व्यक्ति ही सबसे अधिक मायने रखता है। शारीरिक फिटनेस, मानसिक चपलता, तार्किक सोच, तकनीकी कौशल और खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता ही आपको सफलता तय

करेगी।
देश के लिए महत्वपूर्ण और गर्व का अवसर उन्होंने कहा कि यह वास्तव में देश के लिए महत्वपूर्ण और गर्व का अवसर है कि 355 कैडेट अधिकारी के रूप में हमारी गौरवशाली सेना का हिस्सा बन रहे हैं। मैं सेना की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। मित्र देशों के 39 कैडेट को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वह अपने देश को गौरवान्वित करेंगे।

इन्हें मिला पुरस्कार

स्वाट ऑफ ऑनर व स्वर्ण पदक- प्रवीण सिंह, आगरा (उत्तर प्रदेश), रजत पदक मोहित कापड़ी, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), रजत पदक टीजी-विनय भंडारी, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड), कांस्य पदक- शौर्य भट्ट, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर- कोहिमा कंपनी - सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट- मोहम्मद नूर कुतुब-उल-आलम (बांग्लादेश)

भारतीय सेना व असम रायफल को मिले 118 अधिकारी

बिहार के ओटीए गया में शनिवार को रजत जयंती पासिंग आउट परेड के साथ ही भारतीय सेना को 103 और असम राइफल को 15 अधिकारी प्राप्त हुए। परेड का निरीक्षण उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी व कमांडेंट ले. ज. परमजीव सिंह मिह्नास ने किया। इस दौरान अन्य अधिकारी व कैडेटों के स्वजन भी मौजूद थे। उपसेना प्रमुख ले. ज. उपेन्द्र द्विवेदी ने युवा सैन्य अधिकारियों से सेना के मूल्यों, परंपराओं और लोकाचार को बनाए रखने का आह्वान किया।

दिहाड़ी बढ़ाने की राह में केंद्र सरकार, कितना होगा न्यूनतम मजदूरी? सभी राज्यों के लिए होगा मान्य

असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल तय करने जा रही है। केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। श्रम मंत्रालय इस बार न्यूनतम मजदूरी की जगह न्यूनतम जीवनयापन लागत तय करने की तैयारी में है। इस काम में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भी मदद ली जा रही है।

नई दिल्ली। असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल तय करने जा रही है। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अभी राज्य केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। इसलिए केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं।

400 रुपये का वादा पूरा करेगी कांग्रेस?

केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। क्योंकि भाजपा व गैर भाजपा शासित दोनों ही राज्य केंद्र के इस कदम का विरोध नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो अभी लोकसभा

चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपए करने का वादा किया था। श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केंद्र इस मामले में कानून लाने जा रहा है ताकि कोई भी राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दे सके। राज्य केंद्र की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उससे कम नहीं दे सकेगा।

पहले 176 रुपये.. अब कितनी होगी दिहाड़ी?

इससे पहले वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को अपडेट किया था जो मात्र 176 रुपए प्रतिदिन है। श्रम मंत्रालय इस बार न्यूनतम मजदूरी की जगह न्यूनतम जीवनयापन लागत तय करने की तैयारी में है। न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को काम के नाम पर शोषण से बचाने के लिए तय की जाती है जबकि जीवनयापन लागत में रोटी-कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को भी शामिल किया जाता है। राज्य कुशल व गैर कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को अपडेट करते रहते हैं। राज्यों में गैर कुशल श्रमिकों के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी औसतन 7000-12,000 रुपए प्रतिमाह के बीच है। दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 17,200 रुपए प्रतिमाह है।